# महाराष्ट्र की चीनी मिलों को बिना ब्याज के लोन

[ जयश्री भोसले | पुणे ]

चीनी के गिरते दाम की वजह से मिलों के लिए गन्ने का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से गन्ने के भुगतान के लिए इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन देने का प्रोसेस तेज करने को कहा है।

केंद्र सरकार ने देश की शुगर इंडस्ट्री को 6,600 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन देने की मंजूरी दी है। इसमें से महाराष्ट्र की चीनी मिलों को 2,500 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। लोन चुकाने के लिए 2 वर्ष का मोरेटोरियम होगा। इसके बाद मिलों को 3 वर्षों में लोन चुकाना होगा। केंद्र सरकार मिलों की ओर से चुकाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी से इंटरेस्ट का भुगतान करेगी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा को-ऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव (एमएससी) चीनी मिलों को प्रॉडक्शन गिरवी रखने के बदले लोन देता है। बैंक चीनी की कीमतों का वैल्यूएशन कर इस वैल्यू का 85 फीसदी लोन देता है।

**महाराष्ट्र सरकार** ने राज्य में सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से गन्ने के भुगतान के लिए इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन देने का प्रोसेस तेज करने को कहा है

सीजन की शुरुआत में चीनी का वैल्यूएशन 2,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लगाया जा रहा था। इसके आधार पर बैंक ने 2,280 रुपये प्रति क्विंटल पर लोन दिया, जिसमें से 1,530 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के भुगतान के लिए था। अब चीनी की कीमत गिरकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई है। गन्ने की बकाया रकम के भुगतान के लिए बैंक से केवल 1,410 रुपये प्रति क्विंटल की रकम उपलब्ध है। कई मिलों का फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस (एफआरपी) 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा है।

शुगर कमिश्नर विजय सिंघल ने कहा, 'हमने लोन प्रोसेस तेज करने की समीक्षा के लिए मीटिंग की है।' पेराई सीजन दूसरी छमाही में है और इस वजह से गन्ने की पेमेंट का मुद्दा मिलों के लिए और मुश्किल हो गया है। आमतौर पर पेराई के सीजन के अंत में गन्ने की डिलीवरी करने वाले किसानों की पेमेंट में देरी होती है क्योंकि मिलों के ऑपरेशन बंद करने के बाद कोई बैंक लोन उपलब्ध नहीं होता।

सांगली के राजारामबापू पाटिल शुगर को-ऑपरेटिव के मैनेजिंग डायरेक्टर पांडुरंग पाटिल ने बताया, 'हमारे सामने शॉर्ट मार्जिन की समस्या है। हमने गन्ने की कीमत चुकाने के लिए सभी अन्य भुगतान रोक दिए हैं।' बैंकों को अभी तक 85 को-ऑपरेटिव मिलों और 16 प्राइवेट मिलों से लोन प्रपोजल मिले हैं।

Economic Time

14/2/14